Seventeenth Loksabha

an>

Title: Role of Pubjab Farmers in connection with Farm Law.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): सर, सारा सदन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पंजाब को ग्रेनरी ऑफ दि कंट्री इसलिए कहा जाता है, क्योंकि पिछले 70 सालों में हमारे देश के अन्न भंडार में व्हीट और राइस का सबसे ज्यादा योगदान पंजाब से आता रहा है। पंजाब के किसानों ने पिछले समय में एक बड़ा आन्दोलन किया, जो सारे देश ने देखा, जिसमें 700 किसान शहीद भी हो गए। जब वह आन्दोलन खत्म करने के लिए 9 दिसम्बर, 2021 को सरकार ने किसानों को कहा था कि हम ये कानून वापस लेते हैं, तब जो चिट्ठी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किसानों को दी थी, उसमें क्लियरली कहा गया था, उसमें नम्बर वन पॉइंट यह था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसका मैंडेट यह होगा कि देश के किसान को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है। यह नम्बर वन पॉइंट था और यह उनका नम्बर वन एजेंडा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हमें एक लीगल राइट दिया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस महीने की 12 तारीख को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से एक गज़ट नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें वे सारी बातें हटाकर, सिर्फ यह लिख दिया गया है – "To make MSP more effective and transparent."

इसको करने के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है, उसमें चेयरमैन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को बना दिया गया, जो उन तीन कानूनों के आर्किटेक्ट थे। उनके साथ नीति आयोग के मेंबर हैं, जो ये काले कानून लेकर आए। उसके बाद, इसमें जो पांच फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने लिखे हैं, उनमें से ... * और अन्य सारे लोग भाजपा के साथ संबंधित हैं। उनमें से एक महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलसी रह चुके हैं। ... * बीजेपी से हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई भी नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: सर, यह रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें जो पांच रिप्रजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स हैं, ये वही लोग हैं, जिन्होंने वोसीफेरसली इन कानूनों के हक में पूरे देश में शोर मचाया था और इनके हक में खड़े थे। उनको इसमें डाल दिया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जम्मू की यूनिवर्सिटी डाल दी, जबलपुर की यूनिवर्सिटी डाल दी। स्टेट गवर्नमेंट्स में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा शामिल की गई हैं, लेकिन जिन किसानों ने लड़ाई लड़ी, पंजाब के न किसान, न सरकार और न हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है।

सर, किसानों को फिर एक बार आन्दोलन पर मत बैठाइए। यह पंजाब के साथ सरासर ज्यादती हो रही है।